गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

PRGI No. UPHIN/25/A1697

PUBLISHED HINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 056
दि. 25.06.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

जनता छोड़िये, अब तो कांग्रेस वालों को भी हमसे ही है उम्मीद, पीएम मोदी ने ली विपक्ष की चुटकी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की चुटकी लेते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता भी मौजूदा केंद्र सरकार से ही उम्मीद रखते हैं. वे गाहे-बगाहे सरकार से कई काम करने की अपील करते हैं. उन्होंने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि ये उम्मीद उन्हीं लोगों से की जाती है जो काम करते हैं और मौजूदा सरकार काम करती है ये डिमांड ही इसका सबूत है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज केवल देश की जनता ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के नेता भी अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता बार-बार कहते हैं कि मोदी जी, यह कर दीजिए, वह कर दीजिए, क्योंकि उन्हें भी भरोसा है कि अगर कोई सरकार काम कर सकती है तो वह मौजूदा सरकार ही है.

एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार की कार्यशैली ने देशवासियों की अपेक्षाओं को काफी बढ़ा दिया है. उन्होंने कहा कि जब सरकार कोई बड़ा काम पूरा करती है तो लोगों की उम्मीदें वहीं खत्म नहीं होतीं, बल्कि वे और बेहतर सुविधाओं तथा तेज विकास की मांग करने लगते हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग इसे असंतोष मानते हैं, लेकिन मैं इसे जनता की बढ़ती आकांक्षा मानता हूं. उम्मीद उसी से की जाती है, जहां लोगों को विश्वास होता है कि उनका सपना पूरा किया जा सकता है.

कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष भी लगातार सरकार से नई-नई मांगें करता रहता है. सिर्फ आम जनता ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी भी कहती रहती है कि मोदी जी, यह काम कर दीजिए, वह

काम कर दीजिए. वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें भी विश्वास है कि यदि कोई सरकार यह काम कर सकती है तो वह हमारी सरकार है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया इस समय बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है. पुराने तौर-तरीकों को चुनौती मिल रही है और वैश्विक स्तर पर तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं.

हालांकि उन्होंने कहा कि हर चुनौती अपने साथ नए अवसर भी लेकर आती है और भारत को इन अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए. उन्होंने देश के युवाओं, स्टार्टअप्स, नवाचार करने वाले उद्यमियों और कारोबारियों से इन अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि सरकार नेशन फर्स्ट की भावना के साथ हर कदम पर उनके साथ खड़ी है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है और आने वाले समय में सुधारों की यह रफ्तार और तेज होगी.

उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना केवल सरकार का नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का सामूहिक संकल्प है और इसी सामूहिक प्रयास से यह लक्ष्य हासिल होगा. उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि आप अपनी आंखों से विकसित भारत देखेंगे. मैं उन लोगों में नहीं हूं जो कहते हैं कि यह काम आने वाली पीढ़ियां देखेंगी. मैं चाहता हूं कि आज की पीढ़ी ही विकसित भारत का सपना साकार होते हुए देखे.

अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने बिना किसी का नाम लिए कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल एक तरफ विकास परियोजनाओं का विरोध करते हैं, जबकि दूसरी ओर उन्हीं परियोजनाओं जैसी सुविधाओं की मांग भी करते हैं. उन्होंने विशेष रूप से युवाओं, खासकर जेन-जी, से ऐसे विरोधाभासी और भ्रामक तर्कों को पहचानने की अपील की.

पीएम मोदी को ईरान के राष्ट्रपति का निमंत्रण, खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्म में आने का अनुरोध

(जीएनएस)।

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है. हालांकि पीएम मोदी को न्योता देने के बारे में नई दिल्ली से कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है. ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्में 5 से 9 जुलाई तक होंगी. 5, 6 और 7 जुलाई को तेहरान और कोम में विशेष समारोह होंगे, जबकि अंतिम श्रद्धांजलि कार्यक्रम 9 जुलाई को मशहद में आयोजित किया जाएगा.

28 फरवरी को अमेरिका के हमले में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी. खामेनेई ने करीब तीन दशकों तक ईरान पर

शासन किया. उनके निधन के बाद यह पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय समारोह होगा, जिसमें दुनिया के कई देशों के नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है.

भारत ईरान को अपना विस्तारित पड़ोसी मानता है. साथ ही, दोनों देशों के बीच प्राचीन और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं. खामेनेई के निधन पर भारत ने गहरा शोक जताया था. पश्चिम एशिया में 40 दिनों तक चले संघर्ष के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ईरानी नेतृत्व से लगातार संपर्क बनाए रखा. वहीं हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने नई दिल्ली आए थे. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और एस. जयशंकर से द्विपक्षीय बैठक की थी.

30 हजार करोड़ की परियोजनाओं पर पीएम मोदी की सख्त समीक्षा, साइबर अपराध पर भी जताई गहरी चिंता

(जीएनएस)।

नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'प्रगति' की 52वीं बैठक में 30 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली चार बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने परियोजनाओं में देरी पर चिंता जताते हुए समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बैठक में पीएम गतिशक्ति योजना, टीबी मुक्त भारत अभियान, साइबर अपराध, डिजिटल गिरफ्तारी और ई-जीरो एफआईआर व्यवस्था पर भी चर्चा हुई।

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 'प्रगति' (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) की 52वीं बैठक में करीब 30 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली चार बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी सिर्फ लागत नहीं बढ़ाती, बल्कि लोगों और उद्योगों को समय पर मिलने वाले लाभों से भी वंचित कर देती है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों को लंबित मुद्दों को

मिशन मोड में हल करने और परियोजनाओं की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए।

नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में आयोजित इस बैठक में प्रधानमंत्री ने सड़क, बिजली, औद्योगिक कॉरिडोर और मेट्रो रेल से जुड़ी चार प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया। ये परियोजनाएं चार राज्यों में फैली हुई हैं और क्षेत्रीय संपर्क, आर्थिक विकास तथा जनकल्याण की दृष्टि से अहम मानी जा रही हैं। बैठक में विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, परियोजनाओं की समयसीमा और बाधाओं को दूर करने पर विशेष जोर दिया गया।

विज्ञापन

परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए पीएम ने क्या निर्देश दिए?

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं से जुड़ी सभी जानकारियां, उपयोगिताएं, स्वीकृतियां और जमीनी स्थिति को पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए। इससे रुकावटों की पहले से पहचान की जा सकेगी और वास्तविक समय के आंकड़ों के आधार पर बेहतर फैसले लिए जा सकेंगे।

टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर क्या कहा गया?

बैठक में प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की। उन्होंने इस अभियान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि जागरूकता फैलाने, मरीजों की निगरानी और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए एनसीसी कैडेटों और 'माय भारत' स्वयंसेवकों की एक विशेष टीम बनाई जानी चाहिए।

सहमति, सहयोग पीएम मोदी से मिले जिनपिंग के दूत, बाहर आते ही बुनने लगे चीन-भारत दोस्ती का रोडमैप

(जीएनएस)।

नई दिल्ली: चीन अब भारत के साथ पुराने गिले-शिकवे भुलाकर नई शुरूआत करना चाहता है. जिसकी हिंट खुद शी जिनपिंग के खास और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दी है. वो इस वक्त दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पहले भारतीय ठरअ अजीत डोभाल के साथ ब्रिक्स सम्मेलन में बैठक की. इसके बाद आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले हैं. इस मुलाकात के बाद उन्होंने चीन-भारत के रिश्तों को दोबारा खड़ा करने की वकालत की है. वांग यी का मानना है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के नाते, दोनों देशों को अब आपसी अविश्वास और गलतफहमियों को दूर करना होगा.

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कहा कि चीन भारत के साथ मिलकर दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमति को लागू करने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों को आपसी भरोसा बढ़ाने, गलतफहमियां दूर करने, संवेदनशील मुद्दों को समझदारी से संभालने, पारस्परिक लाभ वाले सहयोग को गहरा करने और द्विपक्षीय संबंधों की सकारात्मक गति को बनाए रखने के लिए साथ काम करना चाहिए. साथ ही, दोनों देश अपने-अपने आधुनिकीकरण के

लक्ष्यों को आगे बढ़ा सकते हैं. बैठक के दौरान वांग यी ने कहा कि चीन और भारत को ग्लोबल साउथ के देशों के बीच एकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में उदाहरण पेश करना चाहिए.

भारत में चीन के राजदूत शू फीहोंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए लिखा, 'चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश मामलों आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी ने नई दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. वांग ने कहा कि चीन और भारत, दुनिया के दो सबसे बड़े विकासशील देश और ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य होने के नाते, ग्लोबल साउथ देशों के बीच एकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं. चीन, ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में भारत की जिम्मेदारियों का समर्थन करता रहेगा और ब्रिक्स सहयोग को मजबूत बनाने के लिए भारत के साथ काम करेगा'.

उन्होंने आगे कहा, 'चीन भारत के साथ मिलकर दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमति को लागू करने, आपसी विश्वास बढ़ाने, संदेह दूर करने, संवेदनशील मुद्दों को सही तरीके से संभालने, आपसी लाभ वाले सहयोग को और मजबूत करने तथा भारत-चीन संबंधों की सकारात्मक दिशा को बनाए रखने के लिए तैयार है. यह दोनों देशों की जनता के मूल हितों के अनुरूप है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की साझा अपेक्षाओं के भी अनुकूल है'. चीनी विदेश मंत्री ने सोमवार को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (ठरअ) अजीत डोभाल से भी मुलाकात की. बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों में हाल की प्रगति की समीक्षा की और माना कि संबंधों के सामान्य होने की दिशा में धीरे-धीरे प्रगति हो रही है.

चीन के राजदूत ने भी संबंधों को आगे बढ़ाने की की वकालत

इस बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिस्री, राजदूत शू फीहोंग और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे. चीन के राजदूत की ओर से सोशल मीडि या प्लेटफॉर्म पर जारी बयान के अनुसार, वांग यी ने कहा कि भारत और चीन, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं, इसलिए दोनों देशों को अपने संबंधों को केवल द्विपक्षीय नजरिए से नहीं, बल्कि दीर्घकालिक और वैश्विक दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए.

'लोकसभा स्पीकर को बागी सांसदों से नहीं मिला कोई लेटर', ओम बिरला से मिलने के बाद उद्धव गुट ने किया दावा

(जीएनएस)।

महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुटो में चल रही वर्चस्व की लड़ाई अब देश की संसद तक पहुंच गई है। उद्धव ठाकरे गुट यानी शिवसेना (यूबीटी) ने लोकसभा में बागी सांसदों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी सिलसिले में उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों और नेताओं ने नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा।

इस मुलाकात के बाद पार्टी सांसद अरविंद सावंत ने बताया किशिवसेना (यूबीटी) के सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा था। जिसमें कहा था कि संविधान की रक्षा आपको करनी है इसलिए बागी गुट को लेकर कोई भी फैसला लेने से पहले हमारा पक्ष जरूर सुना जाए।

अरविंद सावंत ने बताया कि आज हमने फिर से अनुरोध किया है कि शिवसेना के मामले में जल्दबाजी में एकतरफा निर्णय न लिया जाए। लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले दोनों पक्षों की उचित सुनवाई आवश्यक है।

इसके साथ ही अरविंद सावंत ने बताया कि उद्धव ठाकरे धड़े के प्रतिनिधियों ने मुलाकात के दौरान लोकसभा अध्यक्ष से पूछा कि क्या विरोधी गुट की तरफ से किसी

अलग व्यवस्था को लेकर कोई पत्र मिला है? इस पर अरविंद सावंत ने बताया कि स्पीकर ओम बिरला ने साफ किया कि उनके कार्यालय को अभी तक बागी सांसदों के समूह की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक पत्र या दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है जिससे भ्रम की स्थिति बने।

अरविंद सावंत ने बागी धड़े की कानूनी स्थिति पर हमला बोलते हुए कहा कि संविधान के प्रावधानों के तहत बागी सांसदों को किसी अलग गुट के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि संसद के भीतर बागी गुट के लिए अलग से बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। सावंत का मानना है कि ऐसा करना लोकतांत्रिक नियमों और परंपराओं के विपरीत होगा।

मुलाकात में शामिल रहे शिवसेना (यूबीटी) के दूसरे वरिष्ठ नेता अनिल देसाई ने भी इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण कानूनी और संवैधानिक पहलुओं को सामने रखा। देसाई ने स्पष्ट किया कि 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत यदि किसी विधायी दल के पास दो-तिहाई बहुमत भी मौजूद हो, तो भी वह मूल राजनीतिक दल के विलय के बिना खुद को अलग दल घोषित नहीं कर सकता। यदि वे किसी स्थापित दल में स्वयं का विलय नहीं करते हैं, तो उनकी सदस्यता पर संकट खड़ा हो जाएगा। वे स्वतंत्र समूह के रूप में मान्यता की मांग नहीं कर सकते।

अनिल देसाई ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें पूरा भरोसा दिलाया है कि इस मामले में जो भी फैसला होगा, वह पूरी तरह से स्थापित नियम-प्रक्रियाओं के तहत ही तय किया जाएगा। नियमों और संवैधानिक प्रावधानों से इतर कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। बागी गुट की ओर से यदि कोई भी आवेदन आता है, तो लोकसभा सचिवालय पहले उसकी गहन कानूनी पड़ताल करेगा और फिर फैसला लेगा।

यह पूरा विवाद केवल संसद में बैठने की व्यवस्था तक सीमित नहीं है। संसद के भीतर किस गुट को वास्तविक शिवसेना माना जाएगा, इसका सीधा ताल्लुक इस बात से है कि सदन में पार्टी का आधिकारिक व्हिप जारी करने का अधिकार किसके हाथों में रहेगा। व्हिप का उल्लंघन होने पर सांसदों की सदस्यता रद्द हो सकती है, यही वजह है कि दोनों गुट इस मोर्चे पर मुस्तैद हैं।

3 जुलाई से सजेगा यूपी आम महोत्सव 2026, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन, निर्यात और ब्रांडिंग पर होगा विशेष फोकस

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश सरकार 3 से 5 जुलाई तक लखनऊ में यूपी आम महोत्सव 2026 का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। महोत्सव में आम की सैकड़ों दुर्लभ और प्रसिद्ध किस्मों का प्रदर्शन होगा। साथ ही किसानों, बागवानों और निर्यातकों को आधुनिक तकनीक, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और निर्यात के अवसरों की जानकारी दी जाएगी। 4 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बायर-सेलर मीट भी आयोजित होगी।

उत्तर प्रदेश की पहचान केवल देश के सबसे बड़े आम उत्पादक राज्य के रूप में ही नहीं है, बल्कि यहाँ की दशहरी, लंगड़ा, चौसा और रटौल जैसी किस्में दुनिया भर में अपने स्वाद और गुणवत्ता के लिए जानी जाती हैं। प्रदेश के आम को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में अगले महीने लखनऊ में तीन दिवसीय यूपी आम महोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। यह आयोजन आम उत्पादन, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और निर्यात को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सरकार का मानना है कि आम महोत्सव केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि किसानों, बागवानों, निर्यातकों और कृषि उद्यमियों के लिए नए अवसरों का मंच बनेगा। यहाँ आम की दुर्लभ किस्मों के प्रदर्शन के साथ-साथ आधुनिक बागवानी तकनीकों, मूल्य संवर्धन और वैश्विक व्यापार संभावनाओं पर भी चर्चा होगी। इससे प्रदेश के आम को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का आयोजन 3 से 5 जुलाई तक लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा। वहीं 4 जुलाई को जन भवन में अंतरराष्ट्रीय बायर-सेलर मीट आयोजित होगी, जिसमें देश-विदेश के खरीदार, निर्यातक और कृषि उद्यमी भाग लेंगे। उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि यह आयोजन प्रदेश की उद्यानिकी और कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

महोत्सव में उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों के प्रगतिशील बागवान, कृषि विशेषज्ञ, निर्यातक और उद्यमी शामिल होंगे। यहाँ आम की सैकड़ों विशिष्ट और दुर्लभ प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाएगा।

दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली, रटौल और लखनऊ सफेदा जैसी प्रसिद्ध किस्में विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी।

सम्पादकीय

कोचिग सेंटर और एनओसी में गड़बड़

हादसों का मंजर व्यवस्था की लापरवाही, समय अब रस्म- अदायगी से ऊपर उठने का है। जब तक हर कोचिग सेंटर के पास फायर एनओसी, हर व्यावसायिक इमारत के पास सही नक्शा और हर अधिकारी के पास अपनी जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ये आग के हादसे थमने वाले नहीं हैं। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले एक शाश्वत सत्य कहा था कि बुद्धिमान शासक वही है जो आने वाले संकट को पहले से भांप ले और उसके निराकरण का उपाय करे। लेकिन आज के 'लोकतंत्र' में जब हम लखनऊ की उस तीन मंजिला इमारत को 'लाक्षागृह' बनते देखते हैं, जहां 15 मासूम चिराग एक साथ बुझ गए, तो चाणक्य की वह सीख एक तंज की तरह चुभती है। यह महज एक हादसा नहीं है, बल्कि उस प्रशासनिक शीतनिद्रा का परिणाम है जो केवल लाशों के ढेर पर ही जागती है। लखनऊ के अलीगंज में जो हुआ, वह कोई इत्तेफाक नहीं था। यह उस जर्जर और भ्रष्ट व्यवस्था का निचोड़ है, जहां सुरक्षा मानकों को फाइलों के भीतर दफन कर दिया जाता है और भ्रष्टाचार को धरातल पर फलने-पूलने का मौका दिया जाता है। सवाल यह नहीं है कि कोचिग सेंटर में आग क्यों लगी, सवाल यह है कि कोचिग सेंटर वहां क्यों चल रहा था? 2014 में जिस इमारत का नक्शा आवासीय उपयोग के लिए पास हुआ, वह कब और वैसे एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में तब्दील हो गई? 2016 में जब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस अवैध निर्माण को ढहाने का आदेश दिया था, तो महज दो महीने बाद वह आदेश किस 'चमत्कारिक' दबाव में रद्द कर दिया गया? इन 10 वर्षों के अंतराल में 30 इंजीनियर और जोनल अधिकारी उस क्षेत्र से गुजरे, क्या किसी की नजर उस इमारत की अवैध व्यावसायिक गतिविधि पर नहीं पड़ी? आंकड़े चीख-चीख कर कह रहे हैं कि यह लापरवाही का नहीं, बल्कि मिलीभगत का एक सुनियोजित तंत्र है। एलडीए के सूत्रों की मानें तो शहर में 30 हजार से अधिक आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स खड़े हैं और इनके पीछे इंजीनियरों की एक तय 'रेट लिस्ट' काम करती है। एक चार मंजिला अवैध इमारत के निर्माण पर 20 से 25 लाख रुपये की वसूली का खेल चलता है। जब व्यवस्था ही पैसों की नींव पर टिकी हो, तो सुरक्षा की उम्मीद करना ही बेमानी है। लखनऊ का यह हादसा दिल्ली के मालवीय नगर के होटल और बिहार के निजी अस्पताल की घटनाओं की कड़वी यादें ताजा कर देता है। हर बार घटना के बाद सिस्टम का वही पुराना 'सिप्टेड' ड्रामा शुरू होता है। हादसे के अगले ही दिन प्रशासन अति-सक्रिय हो जाता है, सीलिग की कार्रवाई होती है, अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है और वुछ दिनों के लिए एक खौफ का माहौल बनाया जाता है। लेकिन क्या यह समाधान है? कानपुर में 30 से अधिक बड़ी कोचिग संस्थाओं को सील कर देना, प्रयागराज और वाराणसी में धड़ाधड़ कार्रवाई करना यह सब महज एक स्वांग है। अगर यही पुता हादसे से पहले दिखाई गई होती, तो उन 15 घरों के बुझ चुके चिराग आज अपनी कक्षाओं में पढ़ रहे होते। ब्रिटिश दार्शनिक एडमंड बर्व ने सही कहा था कि समय पर सावधानी बरतना बाद में पछताने से कहीं बेहतर है। दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहां प्रशासन 'सावधानी' के बजाय 'हादसे' के बाद 'दिखावटी कार्रवाई' को अपनी जिम्मेदारी समझता है। इस पूरे प्रकरण की सबसे दर्दनाक कड़ी वह 'फायरमैन' का वायरल वीडियो है, जिसने व्यवस्था की चूलें हिला दी हैं। एक पढ़ालिखा सिपाही जब अपनी जान जोखिम में डालकर यह आरोप लगाता है कि असली दोषी बड़े अधिकारी हैं, तो सिस्टम का चेहरा और भी घिनौना हो जाता है। जब तक नीचे के कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जाता रहेगा और मलाई खाने वाले अधिकारी सुरक्षित रहेंगे, तब तक जवाबदेही कभी तय नहीं हो पाएगी। मुख्यमंत्री ने मिशन मोड में फायर सेफ्टी ऑडिट के निर्देश दिए हैं, जो स्वागत योग्य है, लेकिन यह ऑडिट कागजों की खानापरूति बनकर न रह जाए, इसकी गारंटी कौन लेगा? क्या हर अस्पताल, नर्सिग होम और कोचिग सेंटर का वास्तविक ऑडिट होगा, या फिर वही पुरानी परंपरा चलेगी जहां एनओसी केवल टेबल के नीचे के लेन-देन से मिल जाती है? अवैध निर्माण की समस्या महानगरों में एक कैंसर की तरह पैल चुकी है।

सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी में बिछा दी ये बिसात, अब क्या करेंगे अखिलेश?

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है. लोकसभा चुनाव में अलीगढ़ संभाग की सभी सीटों पर मिली करारी हार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल ली है. अखिलेश यादव के मजबूत होते 'ढऊआ' समीकरण को भेदने के लिए सीएम योगी ने अलीगढ़ में बड़ा चक्रव्यूह रचा है.

लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की रणभेरी भले ही अगले साल बजनी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (इखढ) ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को तगड़ा झटका लगा था, वहां अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चे की कमान संभाल ली है. लोकसभा चुनाव के दौरान अलीगढ़ संभाग की सभी महत्वपूर्ण सीटों पर मिली हार ने भाजपा आलाकमान के कान खड़े कर दिए थे. इसी मर्म को भांपते हुए सीएम योगी खुद अलीगढ़ पहुंचे और पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉमूर्ले को मटियामेट करने के लिए बिसात बिछा दी है.

अलीगढ़ के इस दौरे को महज एक सरकारी समीक्षा बैठक के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि यह पश्चिमी यूपी में जाट, दलित और ओबीसी मतदाताओं को दोबारा पाले में लाने की भाजपा की एक बहुत बड़ी रणनीतिक शुरूआत है. पिछले लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी और खासकर अलीगढ़ संभाग के तहत आने वाली सीटों पर भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया था. विपक्ष ने यहां ध्रुवीकरण और स्थानीय नाराजगी का ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया कि भाजपा का अभेद्य किला ढह गया.

पश्चिमी यूपी में सीएम योगी का एक्शन प्लान

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ पहुंचकर स्पष्ट कर दिया कि इस क्षेत्र में किसी भी स्तर पर प्रशासनिक लापरवाही या राजनीतिक ढीलापन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने मंडल के अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मैराथन बैठकें कीं ताकि जनता के बीच सरकार की छवि को सुधारा जा सके.

अखिलेश यादव के 'PDA' को ध्वस्त करने का चक्रव्यूह

2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का 'PDA' फॉमूर्ला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेमचेंजर साबित हुआ था. रालोद (RLD) के एनडीए में होने के बावजूद, सपा-कांग्रेस गठबंधन ने दलितों और अति-पिछड़ों के एक बड़े हिस्से को अपने पाले में खींच लिया था. सीएम योगी अब इसी सोशल इंजीनियरिंग की काट ढूंढने निकले हैं.

योगी आदित्यनाथ की रणनीति: सीएम योगी का पूरा ध्यान इस बात पर है कि जो दलित और ओबीसी वोट बैंक भ्रमित होकर विपक्ष की तरफ चला गया था, उसे 'राष्ट्रवाद' और 'सुरक्षा' के मुद्दे पर वापस लाया जाए. इसके लिए वे खुद कानून-व्यवस्था को और सख्त करने और पश्चिमी यूपी के किसानों की समस्याओं का ऑन-स्पॉट निपटारा करने के निर्देश दे रहे हैं.

पश्चिमी यूपी क्यों है बीजेपी के लिए नाक का सवाल?

पश्चिमी उत्तर प्रदेश को यूपी की सत्ता का प्रवेश द्वार कहा जाता है. इस क्षेत्र में लगभग 110 से अधिक विधानसभा सीटें आती हैं. यदि बीजेपी को 2027 में दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है, तो उसे नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मेरठ और मुरादाबाद बेल्ट में एकतरफा क्लीन स्वीप करना होगा.

सीएम योगी के अलीगढ़ दौरे से यह साफ हो गया है कि वे आगामी चुनावों में टिकट बंटवारे से लेकर स्थानीय जातिगत समीकरणों को साधने का रिमोट कंट्रोल खुद अपने हाथ में रखेंगे. उन्होंने स्थानीय नेताओं को साफ हिदायत दी है कि वे गुटबाजी छोड़कर जनता के बीच जाएं. अलीगढ़ से शुरू हुई मुख्यमंत्री की यह सक्रियता आने वाले दिनों में मुजफ्फरनगर, कैराना और मेरठ जैसे संवेदनशील जिलों में भी देखने को मिलेगी, जिससे साफ है कि पश्चिमी यूपी का आगामी चुनाव बेहद आक्रामक और दिलचस्प होने जा रहा है.

पीएम मोदी को लखनऊ के एक्टर ने नजरअंदाज किया?:अनिल रस्तोगी की सफाई- मेरी उम्र की वजह से चूक हुई

(जीएनएस)।

लखनऊ के रहने वाले 82 साल के रिटायर्ड साइंटिस्ट और सीनियर एक्टर अनिल कुमार रस्तोगी को मंगलवार को पद्मश्री पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मानित किया।

अनिल कुमार रस्तोगी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। जिसमें दावा किया गया कि पद्म पुरस्कार समारोह के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि, इस वीडियो को लेकर अनिल कुमार रस्तोगी ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी उम्र की वजह से यह चूक हो गई।

दरअसल, वीडियो में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अनिल रस्तोगी सम्मान लेने के लिए मंच की ओर जाते दिखाई देते हैं। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी ओर हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन रस्तोगी हैंडशेक किए बिना आगे बढ़ जाते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ यूजर्स ने इसे पीएम मोदी को इग्नोर करना बताया।

वीडियो वायरल होने के बाद अनिल रस्तोगी ने खुद सोशल मीडिया पर सफाई दी। एक पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए उन्होंने लिखा, "जो लोग मजाक बना रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि मेरी उम्र 80 साल से ज्यादा है। यह मेरी उम्र की वजह से हुई एक चूक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है और मेरा मानना है कि देश का नेतृत्व करने के लिए वह सबसे बेहतर विकल्प हैं।"

कला और विज्ञान के क्षेत्र में अनिल रस्तोगी के योगदान के लिए उन्हें इस साल पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है।

डॉ. अनिल कुमार रस्तोगी थिएटर और फिल्मों की दुनिया का जाना-पहचाना नाम हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया है और वैज्ञानिक के रूप में भी काम किया है। वे सीएसआईआर के प्रतिष्ठित संस्थान सीडीआरआई, लखनऊ में बायोकेमेस्ट्री विभाग के प्रमुख (हेड) रह चुके हैं और एक वैज्ञानिक के रूप में भी लंबी सेवा दे चुके हैं।

फिल्मी करियर की बात करें तो अनिल कुमार रस्तोगी 'इश्कजादे', 'मुल्क', 'रेड' और 'थप्पड़' जैसी 75 से अधिक फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 14 वेब सीरीज और विभिन्न टीवी धारावाहिकों के करीब 500 एपिसोड में काम किया है। वे 99 नाटकों के लगभग एक हजार मंचन कर चुके हैं।

अनिल रस्तोगी ने वेब सीरीज 'आश्रम' में मुख्यमंत्री (सुंदर लाल) की भूमिका निभाई थी।

कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें पहले भी कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है। डॉ. अनिल रस्तोगी को यश भारती-2017, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार-2023, पाटलिपुत्र लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड-2024, अभ्युदय अंतरराष्ट्रीय शलाका सम्मान-2026 और कालिदास सम्मान मिल चुका है।

बचपन में बेगम साहिबा ने रखा था 'फकीरे' नाम, मां ने बेच दिया था

अनिल रस्तोगी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उनके परिवार में बच्चों के जीवित न रहने की मान्यता के चलते बचपन में उन्हें एक बेगम साहिबा को प्रतीकात्मक रूप से सौंप दिया गया था। उन्होंने उनका नाम 'फकीरे' रखा, जबकि उनके बड़े भाई का नाम 'गुलाम हुसैन' रखा गया। मोहर्रम के दौरान घर में ताजिया रखा जाता था और वह ताबीज पहनकर फकीरी की रस्म निभाते हुए लोगों के घर जाते थे। बेगम साहिबा उन्हें खाने-पीने की चीजें दिया करती थीं।

अक्षय कुमार से कहा- 'मैं भी कभी जवान था' अपने मशहूर हास्य नाटक 'पंछी जा, पंछी आ' को याद करते हुए अनिल रस्तोगी कहते हैं कि यह उनके जीवन के बेहतरीन नाटकों में से एक था। इसी नाटक पर बाद में फिल्म 'गरम मसाला' बनी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में अक्षय कुमार से कहा था, "आज जो किरदार आप निभा रहे हैं, वह मैं बरसों पहले मंच पर कर चुका हूं।" जब अक्षय कुमार हैरान हुए तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, "मैं भी कभी जवान था।"

एक लाइन ने बदल दी फिल्मी किस्मत फिल्म 'इश्कजादे' के ऑडिशन का किस्सा सुनाते हुए रस्तोगी बताते हैं कि उन्हें एक संवाद समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने साथी कलाकार अशोक सिन्हा से मदद मांगी, जिन्होंने उन्हें वह लाइन समझाई, जबकि वे खुद भी उसी रोल के दावेदार थे। दिलचस्प बात यह रही कि अशोक सिन्हा का चयन नहीं हुआ, लेकिन अनिल रस्तोगी को वही भूमिका मिल गई। उनका मानना है कि शायद उसी संवाद ने उनके फिल्मी करियर की दिशा बदल दी।

अनिल रस्तोगी थिएटर भी करते हैं। वे 82 साल के हैं।

पद्मश्री से ज्यादा लोगों का प्यार मिला पद्मश्री सम्मान की घोषणा को लेकर अनिल रस्तोगी कहते हैं कि सम्मान मिलने की खुशी तो थी ही, लेकिन उससे भी बड़ी खुशी इस बात की हुई कि उन्हें देशभर से लोगों का इतना स्नेह मिला। घोषणा के बाद लगातार फोन और संदेश आते रहे, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि लोग उनसे कितना प्यार करते हैं।

लखनऊ जाएं या मुंबई, बिरयानी की फरमाइश तय लखनऊ से अपने जुड़ाव पर वह कहते हैं कि जब भी मुंबई या किसी दूसरे शहर जाते हैं, दोस्त सबसे पहले लखनऊ की बिरयानी मंगवाने की फरमाइश करते हैं।

हालांकि वह खुद नॉनवेज और लहसुन नहीं खाते, लेकिन दोस्तों की यह मांग कभी खत्म नहीं होती। वह बताते हैं कि उनके परिवार का चिकनकारी से भी जुड़ाव रहा है, इसलिए उनके घर का नाम 'चिकन महल' रखा गया।

साइंस और थिएटर दोनों को साथ रखा अनिल रस्तोगी कहते हैं कि एक समय उन्हें सलाह दी गई कि साइंस और थिएटर में से किसी एक को चुन लें। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वह विज्ञान के प्रति अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं छोड़ेंगे। वह दिनभर अपनी वैज्ञानिक जिम्मेदारियां निभाते और बाकी लोग जब परिवार के साथ समय बिताते, तब वह थिएटर के लिए समय निकालते।.

पद्म भूषण से सम्मानित ममूटी पीएम मोदी से मिले

(जीएनएस)।

साउथ सिनेमा, खासकर मलयामल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स में शुमार दिग्गज अभिनेता ममूटी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से खास मुलाकत की। जिसकी तस्वीरें जब सामने आईं, तो परिवार के चेहरे पर खुशी और गर्व दिखा। वहीं, नजरें घर की इकलौती बहुरानी की सादगी पर अटक गईं।

पद्म भूषण से सम्मानित होने के बाद मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ममूटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जहां उनका पूरा परिवार मौजूद रहा, लेकिन नजरें घर की इकलौती बहुरानी पर टिकी रहीं। पीएम मोदी और ममूटी के बेटे, एक्टर दुलकर सलमान ने इस मुलाकत की तस्वीरें शेयर की हैं, जो अब सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच रही है। जहां फिल्मों में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए ममूटी को मिले इस सम्मान की खुशी परिवार के चेहरे पर साफ झलकी।

ऐसे में इस खास मौके को और भी खास बनाने के लिए वे सेरेमनी खत्म होने के बाद पीएम मोदी से मिले। जहां घर की बहू और दुलकर की पत्नी अमल सूफिया का देसी रूप सुंदर

लगा, तो ननद और सासू मां भी अपने-अपने स्टाइल से देसी पहनावे की खूबसूरती को दर्शा गईं। हालांकि, अमल सादगी में भी हीरोइन जैसी अदाएं दिखाकर लाइमलाइट लूट ले गईं। तभी तो उनके लोगों के बीच खूब चर्चे हो रहे हैं।

74 साल के एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर ममूटी को सिनेमा जगत में उनके लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जिसके लिए वह क्रीम कलर के बंदगला के साथ ब्लैक पैंट्स पहन फॉर्मल लुक में राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उनके बेटे दुलकर सलमान भी ब्लैक बंदगला और ग्रे- ब्राउनिश टोन ट्राउजर में पापा के साथ ट्विनिंग कर गए। वहीं, पीएम का हमेशा की तरह सफेद कुर्ता- चूड़ीदार में देसी रूप देखने को मिला। जिसे उन्होंने ब्लैक हाफ जैकेट के साथ पेयर किया और ममूटी के परिवार से मुलाकात की।

अमल यहां बेज- न्यूड टोन का एम्बेलिश्ड सूट पहने हुए हैं, जो उन्हें बेहद सॉफ्ट और एलिगेंट लुक दे रहा है। कुर्ते पर टोन-ऑन-टॉन सेक्विन, बीड्स और थ्रेड वर्क की बारीक कढ़ाई की गई है, जो आउटफिट को रिच फिनिश देती है। वी-नेक को सुनहरे सेक्विन से हाइलाइट करके कुर्ते पर फ्लोरल बेल जैसा खूबसूरत डिजाइन बनाया।

जिसके साथ उन्होंने मैचिंग स्ट्रेट पैंट्स और ऑर्गेंजा का दुपट्टा कैरी किया। जिसे कर्व कट बॉर्डर देकर उसे सितारों से सजाया। जिसमें उनका लुक क्लासी, एलिगेंट और स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बो दिखा गया। टोन-ऑन-टोन कढ़ाई का मतलब इसके नाम से भी पता चलता है। जिस पर सेम टोन के कलर्स का यूज होता है, यानी यह ऐसी कढ़ाई की तकनीक है जिसमें कपड़े और धागे का रंग एक जैसा होता है या बहुत मिलते-जुलते शेड्स को चुना जाता है। इससे डिजाइन में रंगों का कंट्रास्ट नहीं बनता और यह सेम कलर पैलेट को ही निखारती है।

पीएम मोदी पर भी चढ़ा 'पंचायत' का खुमार, 'बिनोद' से मिलते ही पूछ लिया मजेदार सवाल! वीडियो वायरल

(जीएनएस)।

वेब सीरीज 'पंचायत' के किरदार अब सिर्फ ओटीटी दर्शकों तक सीमित नहीं रहे हैं। फुलेरा गांव की कहानी और उसके पात्रों ने देशभर में अपनी अलग पहचान बनाई है। इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है। एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात 'पंचायत' में बिनोद का किरदार निभाने वाले अभिनेता अशोक पाठक से हुई।

खास बात यह रही कि पीएम मोदी ने उनसे मिलते ही सीरीज के चर्चित डायलॉग का जिक्र कर दिया। वीडियो सामने आते ही फैंस के बीच उत्साह बढ़ गया और लोग एक बार फिर बिनोद के किरदार को याद करने लगे। सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की खूब चर्चा हो रही है।

हाल ही में एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात अभिनेता अशोक पाठक और 'पंचायत' में बनराकस का किरदार निभाने वाले भूषण शर्मा से हुई। हाथ मिलाने के दौरान पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए भूषण शर्मा से पूछा, "बिनोद सुनता है कि नहीं सुनता है?" उनकी यह बात सुनते ही वहां मौजूद लोग भी हंस पड़े। कुछ ही देर में इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया।

इस मुलाकात का वीडियो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी साझा किया। वीडियो सामने आने के बाद फैंस लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई यूजर्स ने इसे साल का सबसे दिलचस्प कोलैब बताया। किसी ने लिखा कि बिनोद फिर से छा गया, तो किसी ने इसे थिएटर कलाकारों की बड़ी उपलब्धि बताया। एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि "देख रहा है बिनोद, प्रधानमंत्री जी हमसे कैसे मिल रहे हैं।"

वीडियो के कमेंट सेक्शन में 'पंचायत' से जुड़े कई लोकप्रिय किरदारों का जिक्र देखने को मिला। कुछ लोगों ने फुलेरा गांव की कहानी को याद किया तो कुछ ने सचिव जी और प्रधान जी वाले संदर्भों के साथ मजेदार टिप्पणियां कीं। कई दर्शकों ने लिखा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि देश के प्रधानमंत्री भी सीरीज के इतने लोकप्रिय डायलॉग से परिचित होंगे।

कौन हैं कृष्णावतारम की 'सत्यभामा'? गुजरात की पूर्व सीएम आनंदीबेन से रखती हैं खास कनेक्शन

(जीएनएस)।

मशहूर निर्देशक हार्दिक गज्जर की फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट-1 द हार्ट' की वजह से एक खूबसूरत चेहरा घर-घर लोकप्रिय हुआ है और वो फेस है फिल्म में भगवान कृष्ण की पटरानी सत्यभामा का रोल निभाने वाली संस्कृति जायना का, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से साबित कर दिया कि वो इस फील्ड में भले ही नई हों लेकिन उनका सफर काफी लंबा होने वाला है।

लोग उनकी अदायगी और सुंदरता की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं, आप में से बहुत कम जानते होंगे कि संस्कृति जायना एक फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं बल्कि एक सियासी खानदान से ताल्लुक रखती हैं। उनकी दादी का नाम आनंदीबेन पटेल है, जो कि मौजूदा दौर में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं।

उनकी मां का नाम अनार पटेल है, जो कि एक जानी-मानी सोशल एंटरप्रेन्योर हैं और पिता जयेश पटेल एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। गुजरात

के संभ्रांत परिवार से आने वाली संस्कृति जायना की शुरू से ही रूचि बिजनेस और फैशन इंडस्ट्री से रही है।

उन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में एक फैशन उद्यमी के रूप में अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया था। लंदन से पढ़ाई करने वाली संस्कृति ने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया है और एक धार्मिक फिल्म से रूपहले पर्दे पर डेब्यू किया है।

ऐतिहासिक किरदार काफी लुभाते हैं मुझे

जिसके बारे में बात करते हुए उन्होंने एक इवेंट में कहा था कि ' उन्हें ऐतिहासिक किरदार काफी लुभाते हैं और उनकी भगवान श्रीकृष्ण में गहरी आस्था है इसलिए उन्होंने एक धार्मिक फिल्म के जरिए अपना फिल्मी सफर शुरू करने का फैसला किया।'

दादी आनंदीबेन पटेल ने की पोती की तारीफ

संस्कृति को अपनी दादी आनंदीबेन पटेल से जो प्रतिक्रिया मिली,वह बेहद खास थी। संस्कृति ने खुलासा किया है कि 'जब उनकी दादी ने फिल्म का क्लाइमेक्स देखा, तो वह पूरी तरह निशब्द रह गईं , उन्होंने तब मेरी ओर मुस्कुराकर देखा, तब उनकी आंखों में जो खुशी मेरे लिए थी, वही मेरा सबसे बड़ा अवॉर्ड था।'

बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन और सीक्वल को लेकर उत्सुकता

निर्देशक हार्दिक गज्जर के विजन और संस्कृति जायना के शानदार अभिनय से सजी इस पौराणिक फिल्म 'कृष्णावतारम' ने न केवल कलात्मक रूप से बल्कि व्यावसायिक तौर पर भी झंडे गाड़े हैं। इस भक्तिमय फिल्म ने हाल ही में वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर शानदार 55 करोड़ रुपये से अधिक की कुल कमाई का आंकड़ा पार किया है, पहली फिल्म की इस बंपर सफलता के बाद दर्शकों और फिल्म समीक्षकों के बीच इसके अगले भाग को लेकर बेहद उत्सुकता का माहौल बना हुआ है।

'कृष्णावतारम पार्ट-2' जल्द

इस विषय पर बात करते हुए संस्कृति ने पुष्टि की है कि 'फिल्म का दूसरा भाग यानी 'कृष्णावतारम पार्ट-2' साल 2027 में बड़े पैमाने पर रिलीज होने के लिए तैयार है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस सीक्वल में दर्शकों को कुछ नया देखने को मिलेगा।'

पीएम मोदी से मिले ईरान सुरक्षा परिषद के उपसचिव डॉ. गदीर निजामीपुर

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी डॉ. गदीर निजामीपुर ने मंगलवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वह ब्रिक्स सदस्य देशों की की सिक्योरिटी एजेंसियों के प्रमुखों और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की बैठक के बाद पीएम मोदी से मिले।

इससे पहले, ब्रिक्स देशों की सुरक्षा एजेंसियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में गदीर ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के प्रतिनिधि के लगाए आरोपों को सख्ती से खारिज किया। इतना ही नहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ईरान के खिलाफ मुहिम में उन्होंने अमेरिका और इजरायल का पूरा साथ दिया।

निजामीपुर ने कहा, 'क्षेत्र में हालिया संघर्ष और उसके बाद पैदा हुई परिस्थितियों के लिए अमेरिका और जायोनिस्ट शासन जिम्मेदार है।उन्होंने आरोप लगाया कि होर्मुज

स्ट्रेट में संकट और हमलों की शुरूआत उन्होंने ही की थी। उन्होंने यह भी दावा किया, इन हमलों का एक हिस्सा यूएई की भूमि पर स्थित ठिकानों से संचालित किया गया, और यूएई ने इन कार्रवाइयों में भाग लेते हुए ईरान के नागरिक ढांचे, स्कूलों और अस्पतालों पर हमलों के लिए अपने क्षेत्र का उपयोग करने दिया।'

हम उम्मीद करते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात प्रचार और दुस्साहस की बजाय अच्छे पड़ोसी संबंधों के सिद्धांतों का सम्मान करेगा और शांति, स्थिरता तथा क्षेत्रीय सहयोग का मार्ग चुनेगा।

मिनाब के छात्रों की पोस्टर लहराया

निजामीपुर ने बैठक में एक पोस्टर भी प्रस्तुत किया, जिसमें मिनाब के उन छात्रों को दर्शार्या गया था जिनकी मौत हालिया हमलों में हुई बताई गई। उन्होंने कहा कि यह तस्वीर उन बच्चों का प्रतीक है जो उनके अनुसार अमेरिका द्वारा किए गए हमले के पहले दिन मारे गए थे। ष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (एनएसए) बैठक चल रही है। दो दिन की इस बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। इस बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) शामिल हैं। इसका मुख्य विषय 'दुनिया के सामने मौजूद गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां' है।

PRGI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

अयोध्याः 'गायब' बताए गए चांदी के काकभुशुंडी कारसेवक पुरम में सुरक्षित! रोज होती है पूजा, 200KG चांदी की भी डिटेल

अयोध्या में राम मंदिर को दान में मिली चांदी को लेकर फैली अफवाहों के बीच नया दावा सामने आया है। दावा किया गया है कि गायब बताए जा रहे चांदी के काकभुशुंडी कारसेवक पुरम में चंपत राय के कक्ष में सुरक्षित हैं।

अयोध्याः रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर को दान में मिली चांदी को लेकर पिछले कुछ समय से विभिन्न प्रकार की चचाएं और आरोप सामने आ रहे थे। खास तौर पर चांदी के काकभुशुंडी के गायब होने की बात कही जा रही थी। हालांकि अब इस मामले में नया दावा सामने आया है, जिसके अनुसार चांदी के काकभुशुंडी कहीं गायब नहीं हुए हैं, बल्कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं।

कारसेवक पुरम में सुरक्षित रखे गए हैं काकभुसुंडी

दावे के मुताबिक चांदी के काकभुशुंडी कारसेवक पुरम स्थित चंपत राय के कक्ष में सुरक्षित रखे गए हैं। बताया गया है कि चंपत राय के पूजा स्थल पर प्रतिदिन उनकी विधिवत पूजा-अर्चना भी की जाती है। इसके अलावा चांदी की एक बड़ी माला भी

कारसेवक पुरम में संरक्षित रखी गई है।

200 किलो चांदी की ईंटों का भी किया गया संरक्षण

जानकारी के अनुसार सिंधी समाज द्वारा दान में दी गई लगभग 200 किलो चांदी की ईंटों को भी सुरक्षित रखा गया है। चांदी के संरक्षण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें विशेष प्रक्रिया के तहत परिवर्तित किया गया।

छोटे-छोटे ब्रिक में बदली गई चांदी

दावा किया गया है कि बड़ी चांदी की ईंटों को गलवाकर आधा-आधा किलो वजन के छोटे सिल्वर ब्रिक तैयार कराए गए। इससे उनके संरक्षण और सुरक्षित भंडारण में आसानी हो सके। इस प्रक्रिया में तकनीकी सहयोग के लिए 'मिंट' नामक संस्था की सहायता ली गई।

SBI लॉकर में रखे गए सिल्वर ब्रिक

तैयार किए गए सभी सिल्वर ब्रिक को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के लॉकर में सुरक्षित रखा गया है। दावा किया गया है कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और सुरक्षा को ध्यान में रखकर अपनाई गई।

अफवाहों पर लगा विराम

चांदी के दान और उसके संरक्षण को लेकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में कई तरह की चचाएं चल रही थीं। अब सामने आई जानकारी के बाद इन अफवाहों पर विराम लगने की बात कही जा रही है।

अयोध्या राम मंदिरः अब सीबीआई की भर्ती में गड़बड़ियां सामने आईं

(जीएनएस)।

अयोध्या के राम मंदिर में दान के पैसे के गलत इस्तेमाल की खबरों के बाद, अब सरकार ने एक जांच शुरू की है। रक्ख की पड़ताल में पैसों के लेन-देन और स्टाफ की भर्ती में कई बड़ी कमियां सामने आई हैं। जानकारी मिली है कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने कर्मचारियों की भर्ती एक प्राइवेट एजेंसी के जरिए की थी। ये नियुक्तियां राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों की सिफारिश पर हुई थीं।

राम मंदिरः सुरक्षा और हिसाब-किताब में लापरवाही

मंदिर के कर्मचारियों ने वर्दी पहनने के नियमों और सुरक्षा जांचों को नजरअंदाज किया। इसके अलावा, मंदिर के चारों ओर CCTV निगरानी में भी ढिलाई बरती गई है। अब जांच टीम सोने, चांदी और दूसरे चढ़ावे के कागजात और उनके हिसाब-किताब में मिली गड़बडियों की गहराई से पड़ताल कर रही है। साथ ही, पिछले साल हुए महाकुंभ के दौरान मंदिर में उमड़ी भीड़ को कैसे संभाला गया, इसकी भी जांच की जा रही है।

इस जांच की हर दिन की जानकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जा रही है। जांच पूरी होने के बाद इसकी एक आखिरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

मध्य प्रदेश में अयोध्या मंदिर चढ़ावा का इफेक्ट, खजराना में 80 कैमरे से होगी दान की सिक्योरिटी

अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा के केस को लेकर मंदिरों की बढ़ी सुरक्षा, इंदौर खजराना मंदिर के दान की कड़ी सिक्योरिटी में होगी गिनती.

(जीएनएस)।

इंदौरः इस समय देश में अयोध्या राम मंदिर के कथित चढ़ावा गबन का मुद्दा जोर-शोर से चल रहा है. जिसके बाद देश के अन्य मंदिरों की दानराशि की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है. वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में खजराना गणेश मंदिर में भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है. खबर है कि इंदौर में अब दान पेटियों को भी सीसीटीवी की निगरानी में लाया जा रहा है.

खजराना मंदिर में निकलता है करोड़ों का दान

इंदौर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर में हर 3 महीने में होने वाली दान राशि की गणना में डेढ़ करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का दान प्राप्त होता है. यह राशि मंदिर की प्रबंधन समिति की निगरानी में गणना के बाद बैंक में जमा की जाती है. यहां साल भर में दान राशि का आंकड़ा कई करोड़ रुपए होता है. इसलिए पहले से ही दान राशि की गिनती एक विशेष कक्ष में सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में की जाती है. जब भी दान पेटियां खोली जाती है, तब एक विशेष टीम का गठन किया जाता है, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी और बैंक अधिकारी शामिल होते हैं.

करोड़ों का दान

इंदौर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर में हर 3 महीने में होने वाली दान राशि की गणना में डेढ़ करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का दान प्राप्त होता है. यह राशि मंदिर की प्रबंधन समिति की निगरानी में गणना के बाद बैंक में जमा की जाती है. यहां साल भर में दान राशि का आंकड़ा कई करोड़ रुपए होता है. इसलिए पहले से ही दान राशि की गिनती एक विशेष कक्ष में सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में की जाती है. जब भी दान पेटियां खोली जाती है, तब एक विशेष टीम का गठन किया जाता है, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी और बैंक अधिकारी शामिल होते हैं.

3-4 साल में होती है दान राशि की गणना

उनकी उपस्थिति में दान की गिनती की जाती है. करीब 40 से ज्यादा दान पेटियों से विदेशी मुद्रा सोने चांदी और आभूषण भी निकलते हैं. जिसका बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है, यह गणना साल में तीन से चार बार की जाती है. इस दान राशि से मंदिर के विकास कार्य और संधारण किया जाता है. इसके अलावा खजराना गणेश मंदिर में ऐसे भी दानदाता हैं, जो करोड़ों की रकम से मंदिर में अलग-अलग प्रकल्प विकसित कर चुके हैं.

प्रबंध समिति के प्रमुख कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया "जो दान राशि जमा होती है. उसका बाकायदा ऑडिट किया जाता है. जो इंदौर जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट के अधीन होता है. मंदिर प्रशासन और पुजारी के मताबिक इंदौर में धन राशि से संबंधित कभी कोई शिकायत नहीं आई, क्योंकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है. वही धनराशि की गणना कलेक्टर के निर्देश पर अलग-अलग विभागों के जिम्मेदार अधिकारी और मंदिर प्रशासन से जुड़े लोग करते हैं. जिसमें पुजारियों की भूमिका या भागीदारी नहीं रहती है. इसके अलावा लगभग 80 कैमरों के माध्यम से पूरे परिसर की निगरानी की जाती है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुनिश्चित रहती है.

मध्य प्रदेश में अयोध्या मंदिर चढ़ावा का इफेक्ट, खजराना में 80 कैमरे से होगी दान की सिक्योरिटी

अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा के केस को लेकर मंदिरों की बढ़ी सुरक्षा, इंदौर खजराना मंदिर के दान की कड़ी सिक्योरिटी में होगी गिनती.

(जीएनएस)।

इंदौरः इस समय देश में अयोध्या राम मंदिर के कथित चढ़ावा गबन का मुद्दा जोर-शोर से चल रहा है. जिसके बाद देश के अन्य मंदिरों की दानराशि की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है. वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में खजराना गणेश मंदिर में भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है. खबर है कि इंदौर में अब दान पेटियों को भी सीसीटीवी की निगरानी में लाया जा रहा है.

खजराना मंदिर में निकलता है करोड़ों का दान

इंदौर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर में हर 3 महीने में होने वाली दान राशि की गणना में डेढ़ करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का दान प्राप्त होता है. यह राशि मंदिर की प्रबंधन समिति की निगरानी में गणना के बाद बैंक में जमा की जाती है. यहां साल भर में दान राशि का आंकड़ा कई करोड़ रुपए होता है. इसलिए पहले से ही दान राशि

की गिनती एक विशेष कक्ष में सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में की जाती है. जब भी दान पेटियां खोली जाती है, तब एक विशेष टीम का गठन किया जाता है, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी और बैंक अधिकारी शामिल होते हैं.

उनकी उपस्थिति में दान की गिनती की जाती है. करीब 40 से ज्यादा दान पेटियों से विदेशी मुद्रा सोने चांदी और आभूषण भी निकलते हैं. जिसका बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है, यह गणना साल में तीन से चार बार की जाती है. इस दान राशि से मंदिर के विकास कार्य और संधारण किया जाता है. इसके अलावा खजराना गणेश मंदिर में ऐसे भी दानदाता हैं, जो करोड़ों की रकम से मंदिर में अलग-अलग प्रकल्प विकसित कर चुके हैं.

प्रबंध समिति के प्रमुख कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया "जो दान राशि जमा होती है. उसका बाकायदा ऑडिट किया जाता है. जो इंदौर जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट के अधीन होता है. मंदिर प्रशासन और पुजारी के मताबिक इंदौर में धन राशि से संबंधित कभी कोई शिकायत नहीं आई, क्योंकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है. वही धनराशि की गणना कलेक्टर के निर्देश पर अलग-अलग विभागों के जिम्मेदार अधिकारी और मंदिर प्रशासन से जुड़े लोग करते हैं. जिसमें पुजारियों की भूमिका या भागीदारी नहीं रहती है. इसके अलावा लगभग 80 कैमरों के माध्यम से पूरे परिसर की निगरानी की जाती है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुनिश्चित रहती है.

गुप्त दान से लेकर हीरा-सोना, महाकाल मंदिर में 144 करोड़ का चढ़ावा, लड्डू से आए 65 करोड़

गर्भगृह का विकास शुरू

इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर के गर्भ गृह का इन दिनों चौड़ीकरण किया जा रहा है. जिससे कि भगवान के दर्शन को आसान और सुगम बनाया जा सके. पंडित उदित भट्ट ने चर्चा में बताया "मंदिर के चौड़ीकरण का काम प्रतिदिन ऋक्कटर कॉलेज के सिविल विशेषज्ञों की निगरानी में किया जा रहा है. गर्भ गृह के सामने की जमीन को भी थोड़ा नीचे किया जा रहा है, ताकि पीछे खड़े हुए भक्तों को भी दर्शन आसानी से हो जाए.

अयोध्या ग्राउंड रिपोर्ट : तपती गर्मी के बीच राम की पैड़ी में फिर लौटा 'सरयू जल', श्रद्धालुओं के चेहरे खिले, रौनक वापस

(जीएनएस)।

चिलचिलाती गर्मी और उमस के बीच अयोध्या आने वाले रामभक्तों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है. राम की पैड़ी पर पिछले कई दिनों से थमा हुआ पानी का बहाव एक बार फिर पूरी रफ्तार से बहाल कर दिया गया है. सिल्ट सफाई के कारण बंद किए गए इस जल प्रवाह के दोबारा शुरू होते ही घाटों पर आस्था की रौनक लौट आई है. अब देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालु सुरक्षित माहौल में

पवित्र स्नान और दर्शन-पूजन का आनंद ले पा रहे हैं, जिससे सरयू तट पर बढ़ने वाला हादसों का जोखिम भी टल गया है.

अरविंद केजरीवाल के अयोध्या दौरे पर क्यों भड़का संत समाज? प्रशासन तक पहुंचा मामला

आम आदमी पारी के संयोजक 26 जून को अयोध्या पहुंच रहे हैं. राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के विवाद के बीच उनके अयोध्या दौरे पर विवाद खड़ा हो गया है. अयोध्या के संत समाज ने अरविंद केजरीवाल के अयोध्या दौरे का विरोध शुरू कर दिया है. विरोध करने वाले संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उनके दौरे पर आपत्ति जताई है.

(जीएनएस)।

अयोध्या. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 26 जून को अयोध्या दौरे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. एक ओर जहां केजरीवाल रामलला के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए अयोध्या पहुंचने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर संत समाज और पुरोहित समाज का एक वर्ग उनके दौरे का विरोध कर रहा है. विरोध करने वाले संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उनके दौरे पर आपत्ति जताई है.

अयोध्या में पांडा पुरोहित समाज और सनातन रक्षा दल समेत कुछ संगठनों ने अरविंद केजरीवाल के प्रस्तावित दौरे का विरोध किया है. इन संगठनों का आरोप है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं ने पहले भगवान राम और राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिए थे, इसलिए उनका अयोध्या आगमन राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है. पांडा पुरोहित समाज के अध्यक्ष राजेश महाराज ने कहा कि अगर रामलला हैं ही नहीं, जैसा पहले कहा गया था, तो फिर अयोध्या आने की क्या आवश्यकता है? अगर राम हृदय में हैं तो वहीं से दर्शन कर लें. अभी राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े मामले की जांच चल रही है, ऐसे समय में किसी भी तरह की राजनीतिक बयानबाजी माहौल को प्रभावित कर सकती है.

अयोध्या आस्था का केंद्र

पांडा पुरोहित समाज के अध्यक्ष राजेश महाराज ने कहा कि अयोध्या सनातन आस्था का केंद्र है और यहां किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए और किसी भी नेता को इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. सनातन रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुंद माधव त्रिपाठी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण राम मंदिर आ रहे हैं. उनके नेताओं द्वारा लगातार आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया जाता. हमने प्रशासन को ज्ञापन देकर मांग की है कि उनके दौरे पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे धार्मिक उन्माद और अशांति फैलने की आशंका है.

सनातन रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुंद माधव त्रिपाठी ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि केजरीवाल के दौरे से कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केजरीवाल अयोध्या आते हैं तो उनका विरोध किया जाएगा.

मृत आदमी का बयान लिया-पूर्व तहसीलदार समेत 8 तलब:अयोध्या में मौत के 2 साल बाद तहसील में दर्ज हुआ, 23 जुलाई को सुनवाई

(जीएनएस)।

अयोध्या में बीकापुर तहसील में वरासत दर्ज कराने के नाम पर बड़ा फजीर्वाड़ा सामने आया है। जिस व्यक्ति की मौत वर्ष 2017 में हो चुकी थी, उसका बयान दो साल बाद 2019 में तहसील के अभिलेखों में दर्ज दिखाकर वरासत का आदेश पारित कर दिया गया। मामले की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आने पर अदालत ने इसे गंभीर मानते हुए तत्कालीन तहसीलदार, लेखपाल समेत आठ लोगों को तलब किया है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधांशु शेखर उपाध्याय ने प्रथम दृष्टया जालसाजी, कूटरचना और धोखाधड़ी के आरोपों को गंभीर मानते हुए आरोपियों को 23 जुलाई को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।

2017 में मौत, 2019 में दर्ज हुआ बयान

शिकायतकर्ता राजकुमार की ओर से अधिवक्ताओं जय प्रकाश, प्रमोद यादव, गिरीश कुमार और चंद्रशेखर सिंह ने न्यायालय को बताया कि वरासत वाद में रामखेलावन का बयान 16 दिसंबर 2019 को दर्ज दिखाया गया है।

जबकि उपलब्ध मृत्यु प्रमाण पत्र

के अनुसार रामखेलावन की मृत्यु 21 जुलाई 2017 को ही हो चुकी थी। आरोप है कि मृत व्यक्ति को जीवित दिखाकर सुनियोजित तरीके से वरासत की पूरी प्रक्रिया तैयार की गई और सरकारी अभिलेखों में फर्जी दस्तावेज शामिल किए गए।

लेखपाल की रिपोर्ट पर उठे सवाल

मामले में तत्कालीन हल्का लेखपाल भीम सिंह की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। आरोप है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट और वंशावली में भी रामखेलावन को जीवित दशार्या। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर तत्कालीन तहसीलदार दिविजय सिंह ने 20 दिसंबर 2019 को वरासत आदेश पारित कर दिया।

अपील में खुली फजीर्वाड़े की परतें

बाद में मामला अपील के जरिए उप जिलाधिकारी बीकापुर के न्यायालय पहुंचा। जांच के दौरान राजस्व अभिलेखों और दस्तावेजों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद 2 मई 2022 को विवादित वरासत आदेश निरस्त कर दिया गया।

जांच में यह भी सामने आया कि पूरी प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी करते हुए दस्तावेज तैयार किए गए थे।

पूर्व तहसीलदार समेत 8 लोगों को समन

न्यायालय ने मामले में अजय, मथाराम, खदेरू, लालता प्रसाद, मायाराम वर्मा, तत्कालीन लेखपाल भीम सिंह, तत्कालीन पेशकार और तत्कालीन तहसीलदार दिविजय सिंह को तलब किया है।

इन सभी के खिलाफ जालसाजी, कूटरचना, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। अदालत के इस आदेश के बाद बीकापुर तहसील में हड़कंप मच गया है और मामला राजस्व विभाग में चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है।

राजस्व व्यवस्था पर उठे सवाल

मामले ने तहसील स्तर पर दस्तावेजों के सत्यापन और राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि जिस व्यक्ति की मौत दो वर्ष पहले हो चुकी थी, उसका बयान सरकारी रिकॉर्ड में कैसे दर्ज हो गया और उसके आधार पर आदेश भी पारित कर दिया गया।

सीएम योगी का हेलीकॉप्टर एएमयू में उतरने पर छात्र ने उठाए सवाल... कहा कुछ तो शर्म करो; सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

(जीएनएस)।

अलीगढ़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के क्रिकेट मैदान में उतरने पर यूनिवर्सिटी के विदेशी भाषा विभाग के छात्र अजीमुर रहमान ने सवाल उठाए हैं। कहा है, मुख्यमंत्री वैसे तो एएमयू को लेकर बयानबाजी करते हैं। अलीगढ़ आते हैं तो यहां की जमीन का इस्तेमाल करते हैं। 'कुछ तो शर्म करो।'

सोशल मीडिया पर बयान का वीडियो जारी कर छात्र ने कहा है कि यहां के सांसद सतीश गौतम एएमयू के खिलाफ जहर उगलते हैं। आतंकवादी, देशद्रोही कहते हैं। योगी आदित्यनाथ जब भी अलीगढ़ आते हैं, एएमयू में उतरते हैं। 'योगी आदित्यनाथ जी आपकी शर्म कहां चली जाती है।

जिस यूनिवर्सिटी के खिलाफ आप बोलने से बचते नहीं हैं, हमेशा उसी यूनिवर्सिटी की जमीन पर उतरते हैं। कोई तो शर्म होनी चाहिए।' सवाल किया है कि आप इतने असुरक्षित क्यों हो जाते हैं, जब यहां का प्रशासन मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारता है। इसकी वजह बताएंगे? मैं जिस शहर में रहता हूं, वहां रात भर भजन चलता है। कांवड़ यात्रा पर आप इतना गाना-बजाना करते हो, डीजे बजता है।

यह वीडियो भी देखें

किसी मुस्लिम को तो इससे परेशानी नहीं होती, उन्हें तो असुरक्षा फील नहीं होती। आपको असुरक्षा अजानों से फील क्यों होने लगती है। ये तो हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं। छात्र का यह बयान इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है।

महिला प्रोफेसर से कर चुका है बदसलूकी

एएमयू प्राक्टर प्रो. नवेद खां के अनुसार छात्र वीएम हाल में रहता है। वह एमए चाइनीज का छात्र है। बुधवार देर रात ही वीडियो की जानकारी मिली है। इसकी जांच की जा रही है। छात्र ने कुछ दिन पहले ही एक महिला प्रोफेसर से बदसलूकी थी। आरोपित एक बिना नंबर की एक्टिवा के साथ पकड़ा गया था। सुरक्षागार्डों से भी बदसलूकी कर चुका है। इस मामले की पहले से ही जांच चल रही है, कार्रवाई की जाएगी।

हिंदी के उत्कृष्ट प्रयोग के लिए पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल को मिले तीन पुरस्कार

(जीएनएस)।

लखनऊ। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक बुधवार को डालीबाग स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की ओर से परिसर में आयोजित की गई। इसमें पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल को हिंदी के उत्कृष्ट प्रयोग के लिए तीन पुरस्कार मिले।

पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के पीआरओ महेश गुप्ता ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय को सरकारी कामकाज में राजभाषा के अधिकतम प्रयोग के लिए द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। पत्रिका प्रकाशन में चतुर्थ और सर्वाधिक हिंदी कार्यशाला आयोजन में प्रथम पुरस्कार भी मिला। बैठक की अध्यक्षता भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के निदेशक एसएन सुशील ने की। एसएनसुशील ने गत वर्ष अक्तूबर से बीते मार्च की अवधि के लिए पुरस्कार प्रदान किए हैं। डीआरएम गौरव अग्रवाल ने शील्ड और प्रशस्ति पत्र प्राप्त किए। उन्होंने बैठक में उपस्थित 74 केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के प्रमुखों को संबोधित किया। श्री अग्रवाल ने कहा कि मंडल कार्यालय में सरकारी कामकाज नियमानुसार हिंदी या द्विभाषी रूप में हो रहा है। यह स्थिति सतत निगरानी और अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रेरित करके प्राप्त की गई है। आगे बताया कि हिंदी में पांच तकनीकी संगोष्ठियां, 31 हिंदी कार्यशालाएं और एक साहित्यिक संगोष्ठी आयोजित की गई। लखनऊ मंडल कार्यालय और विशिष्ट स्टेशनों पर साहित्यकारों की जयंतियां तथा तकनीकी संगोष्ठियां नियमित रूप से होती हैं।

पीएम मोदी पर की आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट, तेलंगाना के हसन पर चंडीगढ़ अदालत में चलेगा मुकदमा

(जीएनएस)।

चंडीगढ़। इंटरनेट मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विवादित, भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट डालने के आरोपित तेलंगाना निवासी हसन मोहिउद्दीन सिद्दीकी(42) के खिलाफ अब चंडीगढ़ जिला अदालत में मुकदमा चलेगा।

पुलिस ने आरोपित के खिलाफ जिला अदालत में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 318, 336(1), 336(3), 336(4), 340, 353, 356 के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी है। उसके खिलाफ 26 जून से इस केस की सुनवाई शुरू होगी। हसन को चंडीगढ़ पुलिस ने 25 अप्रैल को गिरफ्तार किया था और तब से वह जेल में ही है।

दो बार उसकी जमानत अर्जी जिला अदालत से खारिज हो चुकी है। उसके अलावा मशहूर लेखिका दिल्ली निवासी 74 वर्षीय मधु किश्वर ने भी ऐसी ही टिप्पणी की थी। सेक्टर-26 थाना पुलिस ने हसन और मधु समेत छह लोगों के खिलाफ दो महीने पहले

एफआइआर दर्ज की थी। हसन तो पकड़ा गया था, लेकिन मधु किश्वर को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है।

पूर्व पार्षद की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला

मामले की शुरूआत 19 अप्रैल को हुई थी, जब पूर्व भाजपा पार्षद और एडवोकेट सतिंदर सिंह ने चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कई इंटरनेट मीडिया यूजर्स प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आपत्तिजनक वीडियो भ्रामक कैप्शन के साथ वायरल कर रहे हैं।

शिकायत में मधु किश्वर और हसन सिद्दीकी के समेत छह सोशल मीडिया हैंडल्स का नाम लिया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार मूल वीडियो पहले अमेरिका निवासी एक इंटरनेट मीडिया इन्फ्लूएंसर ने अपलोड किया था।

आरोप है कि बाद में उसी वीडियो को प्रधानमंत्री मोदी से जोड़कर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इस मामले में सेक्टर-26 थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता(बीएनएस) और आइटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआइआर दर्ज की थी।

आरोपित दे रहा यह दलीलें

आरोपित बार बार यही दलील दे रहा है कि उसने प्रधानमंत्री पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की थी। उसने तो बस उस भ्रामक वीडियो को इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस "ग्रोक" से पूछा थी कि क्या यह वीडियो असली है। बस इसी पोस्ट के कारण पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।

झींकपानी चाईबासा सीमेंट कारखाना बचाने की पीएम से भावुक अपील, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक की पत्नी ने लिखा पत्र

(जीएनएस)।

चाईबासा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के झींकपानी स्थित चाईबासा सीमेंट कारखाने को स्थायी रूप से बंद करने के निर्णय पर फिर से विचार की मांग तेज हो गई है।

कारखाने के सेवानिवृत्त महाप्रबंधक (लफे) सुरेंद्र सिंह की पत्नी वाराणसी निवासी किरण सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भावुक पत्र लिखकर इसे पुनर्जीवित करने की मार्मिक अपील की है।

हजारों परिवारों और आदिवासी समाज की जीवनरेखा

किरण सिंह ने अपने पत्र में इस संयंत्र को क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, आदिवासी समाज और हजारों परिवारों की जीवनरेखा बताया है। उन्होंने लिखा कि उनके पति ने इस कारखाने में 38 वर्षों तक अपनी सेवाएं दीं।

उन्होंने इस उद्योग को केवल एक व्यावसायिक इकाई नहीं, बल्कि पूरे कोल्हान क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास का आधार बनते देखा है।

केंद्र व राज्य सरकार

संयंत्र परिसर में बने 900

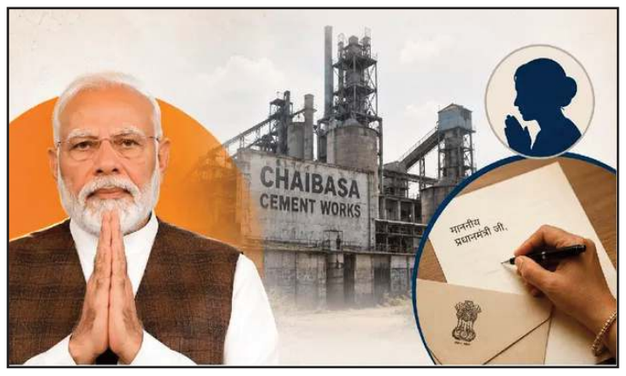

पत्र में वर्ष 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किए गए विस्तारीकरण का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया कि तब 4,000 टन क्षमता की क्लिंकर इकाई स्थापित होने से उत्पादन बढ़ा था और करीब 2,000 लोगों को रोजगार मिला था।

प्रशासनिक अड़चनें दूर करे

आवासीय क्वार्टर आज भी इसकी मजबूत संरचना की गवाही देते हैं। किरण सिंह ने प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा कि खनन पट्टों के नवीनीकरण से जुड़ी कानूनी समस्याएं ही इस बंदी का मुख्य कारण रही हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि यदि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर साझा प्रयास करें, तो इस समस्या का समाधान पूरी तरह संभव है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और आदिवासी विकास की भावना के अनुरूप इस उद्योग को दोबारा चालू कराने की मांग की।

विदा होने से पहले कारखाने में लौट आए जीवन

पत्र के अंत में किरण सिंह ने लिखा कि इस कारखाने की आवाज ने उनके परिवार का पालन-पोषण किया और आज इसे खामोश देखकर उनका मन दुखी है। उन्होंने प्रधानमंत्री से भावुक अपील करते हुए कहा कि हमारी पीढ़ी के इस दुनिया से विदा होने से पहले, चाईबासा सीमेंट कारखाने में एक बार फिर जीवन, रोजगार और उम्मीदों की गूंज लौटाई जाए। उन्होंने बाबा विश्वनाथ से प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त की।

वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर बड़ा विवाद! पाकिस्तान से उठ रहे हैं कई गंभीर सवाल?

(जीएनएस)।

भारतीय क्रिकेट टीम में पहली बार शामिल किए गए युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी 26 जून को आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट में होने वाले पहले टी-20 मैच के जरिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर सकते हैं। हालांकि, उनके इस ऐतिहासिक डेब्यू से ठीक पहले उनकी उम्र को लेकर सरहद पार से एक नया विवाद खड़ा हो गया है।

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज तनवीर अहमद ने एक पाकिस्तानी मीडिया चैनल पर दावा किया है कि वैभव की वास्तविक उम्र 15 वर्ष नहीं, बल्कि कम से कम 21-22 वर्ष है। क्रिकेट जगत में दमदार प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों की उम्र और उनकी शारीरिक परिपक्वता को लेकर अक्सर इस तरह के सवाल उठते रहे हैं। वैभव ने हाल ही में घरेलू और बड़े स्तर के टूनार्मेंट्स में जिस तरह की ताकत और पावर-हिटिंग का प्रदर्शन किया है।

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद ने वैभव की उम्र पर सवाल उठाते हुए अपने दावों के पीछे एक अजीबोगरीब तर्क दिया है। तनवीर ने कहा कि मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि वैभव सिर्फ 15 साल

के हैं। उनका जो मजबूत बेस है और जिस तरह का बैट स्विंग है, वह इस उम्र में मुमकिन नहीं है। वे कम से कम 21 या 22 साल के हैं, क्योंकि 15 साल के बच्चे के लिए इतनी आसानी से लंबे छक्के मारना नामुमकिन है।

वैभव को दी ये नसीहत

उन्होंने वैभव की बल्लेबाजी शैली की आलोचना करते हुए कहा कि वे बिल्कुल 'टेप बॉल' क्रिकेटरों की तरह खेलते हैं, जहां तकनीकी रक्षात्मक खेल के बजाय हर गेंद पर बड़े शॉट्स खेलने की प्रवृत्ति होती है। तनवीर अहमद ने वैभव को अंतरराष्ट्रीय पिचों पर खेलने को लेकर एक बड़ी प्रशासनिक चेतावनी भी जारी की। उनके मुताबिक अभी वैभव बहुत युवा हैं और उनकी आंखें काफी तेज हैं, लेकिन जिस दिन वे आउट ऑफ फॉर्म होंगे, उन्हें अपनी बल्लेबाजी में मौजूद तकनीकी खामियों के कारण गेंद ढूंढना मुश्किल हो जाएगा।

पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज ने दावा किया कि वैभव के पास ठोस पारंपरिक तकनीक नहीं है और यदि विपक्षी गेंदबाजों ने उन्हें मिडिल स्टंप से बाहर (ऑफ-स्टंप की लाइन पर) गेंदें डालीं, तो वे आसानी से जाल में फंस जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे वैभव के टैलेंट को तभी सच मानेंगे जब वे इंग्लैंड जैसी चुनौतीपूर्ण पिचों पर रन बनाएंगे।

आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप

हाल ही में संपन्न हुए आईपीएल 2026 में वैभव ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा 776 रन बनाए और ऑरेंज कैप अपने नाम की। इस दौरान उन्होंने एक ही सीजन में 72 छक्के जड़कर दिग्गज क्रिस गेल का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया था। इंडिया-ए की तरफ से खेलते हुए श्रीलंका-ए के खिलाफ फाइनल मुकाबले में उन्होंने मात्र 29 गेंदों में 94 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इस दौरान उन्होंने महज 11 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो लिस्ट-ए क्रिकेट इतिहास का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है।

यूपी में लेट मानसून ने बढ़ाई टेंशन! खरीफ सीजन बचाने के लिए सीएम योगी का क्या मास्टरप्लान? 75 जिलों में अलर्ट

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश में मानसून की देरी ने खेती-किसानी से लेकर प्रशासनिक तैयारियों तक दबाव बढ़ा दिया है। दक्षिण-पश्चिम मानसून के पूर्वी उत्तर प्रदेश में करीब 28 जून के आसपास पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जबकि सामान्य तौर पर यह इससे लगभग 12 दिन पहले दस्तक दे देता है। इसी अनिश्चितता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागों को खरीफ सीजन के लिए बीज, खाद, सिंचाई, फसल ऋण और किसान सलाह सेवाओं को पहले से दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा से जुड़े विभागों की समीक्षा बैठक में साफ कहा कि मौसम का मिजाज अब पहले जैसा अनुमानित नहीं रह गया है। कभी बारिश देर से आती है, कभी कम दिनों में तेज बारिश हो जाती है और बीच-बीच में सूखे जैसे हालात बनते हैं। ऐसे में सरकार की तैयारी केवल सामान्य मानसून को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि असामान्य बारिश, लू, उमस और संभावित शुष्क दौर को देखते हुए होनी चाहिए।

यूपी मानसून में देरी क्यों अहम है?

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े कृषि राज्य में खरीफ की बुआई काफी हद तक मानसून के समय और फैलाव पर निर्भर करती है। धान की नर्सरी, रोपाई, मक्का, दलहन, तिलहन और सब्जियों की खेती के लिए शुरूआती बारिश बहुत मायने रखती है। अगर बारिश कुछ दिन भी पीछे खिसकती है, तो किसान बुआई के फैसले टालते हैं और खेत की तैयारी, मजदूरी, सिंचाई और बीज की व्यवस्था प्रभावित होती है।

मौसम संबंधी आकलन के अनुसार, मानसून की रफ्तार बिहार के आसपास धीमी पड़ने से उत्तर प्रदेश में इसकी एंट्री अटक गई थी। अब इसके आगे बढ़ने की स्थिति बनी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में शनिवार शाम से बादल बढ़ने और रविवार के बाद मानसून के लिए अधिक अनुकूल हालात बनने की उम्मीद है। हालांकि, उससे पहले क्षेत्र के कई हिस्सों में लू और उमस लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में बुधवार से शुक्रवार तक गर्मी का असर बने रहने की आशंका है। कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है। अधिक नमी के कारण वास्तविक तापमान से ज्यादा गर्मी महसूस हो सकती है और हीट इंडेक्स 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.7 डिग्री अधिक था।

सोमवार (23 जून) को हुई हल्की बारिश से थोड़ी उम्मीद जरूर बनी थी, लेकिन अगले दिन लोगों को खास राहत नहीं मिली। दिन के समय उमस और तेज धूप ने गर्मी को और कठिन बना दिया। यही स्थिति किसानों के लिए भी चुनौती बनती है, क्योंकि खेत में नमी पर्याप्त न हो तो धान की रोपाई या बारिश आधारित बुआई शुरू करना जोखिम भरा हो जाता है।

खरीफ तैयारी में बीज, खाद और सिंचाई पर सबसे ज्यादा फोकस

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से खरीफ अभियान को मिशन मोड में चलाने को कहा है। निर्देश दिए गए हैं कि हर जिले में गुणवत्तापूर्ण बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें और किसानों को उनके लिए अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें। खरीफ सीजन में समय पर बीज मिलना इसलिए जरूरी है क्योंकि देरी होने पर किसान कम अवधि वाली किस्मों की ओर जाते हैं या कई बार बुआई का रकबा घटा देते हैं।

खाद की उपलब्धता पर भी खास जोर दिया गया है। बारिश शुरू होते ही उर्वरकों की मांग अचानक बढ़ जाती है, खासकर उन जिलों में जहां धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है। अगर इस समय वितरण व्यवस्था कमजोर रही, तो खेत तैयार होने के बावजूद किसान रोपाई या बुआई में पीछे रह सकते हैं। मुख्यमंत्री ने खाद की आपूर्ति और वितरण की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।

सिंचाई की व्यवस्था इस बार और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मानसून देर से आने पर नर्सरी बचाने और खेत में नमी बनाए रखने के लिए किसान ट्यूबवेल, नहर या पंपिंग सेट पर अधिक निर्भर होते हैं। इससे डीजल, बिजली और पानी की मांग बढ़ती है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह अतिरिक्त खर्च सीजन की शुरूआत में ही आर्थिक दबाव पैदा कर सकता है।

फसल ऋण को लेकर भी सरकार ने सतर्कता बरतने को कहा है। खरीफ की शुरूआत में किसानों को बीज, खाद, मजदूरी, सिंचाई, डीजल और खेत की तैयारी के लिए नकद जरूरत होती है। अगर संस्थागत ऋण समय पर नहीं मिलता, तो कई किसान महंगे निजी कर्ज की ओर चले जाते हैं। इससे पूरी फसल अवधि में उनकी लागत और जोखिम दोनों बढ़ जाते हैं।

कम बारिश हुई तो क्या रास्ता किसानों के पास?

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कृषि विभाग ने कम बारिश या सूखे जैसे हालात को ध्यान में रखते हुए आकस्मिक कार्ययोजना तैयार की है। ऐसी योजनाओं में आम तौर पर वैकल्पिक फसलों की सलाह, कम अवधि वाली किस्में, बीज व्यवस्था, सिंचाई सहायता, कीट-रोग प्रबंधन और जिला स्तर पर अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय शामिल होता है।

यह कार्ययोजना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश एक जैसी नहीं होती। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून पहले पहुंच सकता है, जबकि मध्य और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का समय और तीव्रता अलग हो सकती है। किसी जिले में तेज बारिश से जलभराव की समस्या बनती है, तो दूसरे जिले में कम बारिश से नमी की कमी रह सकती है।

धान की खेती सबसे ज्यादा संवेदनशील मानी जाती है, क्योंकि इसकी नर्सरी और रोपाई दोनों के लिए पानी की जरूरत होती है। अगर मानसून देर से आता है, तो किसान रोपाई की तारीख बदलते हैं।

मानसून की पहली बारिश में हुई पानी-पानी, दादर, बांद्रा और अंधेरी तक थम गया ट्रैफिक, आईएमडी का रेड अलर्ट

(जीएनएस)।

मुंबई में दस्तक देते ही मानसून ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। पिछले 24 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण देश की आर्थिक राजधानी के कई हिस्सों में जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। बांद्रा, अंधेरी, दादर, मीरा रोड और भायंदर जैसे प्रमुख इलाकों में भारी जलभराव के कारण सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बीच स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है।

मानसून की इस पहली बड़ी बारिश के कारण महत्वपूर्ण अंडरपास और सबवे में पानी भर जाने से यातायात को डायवर्ट करना पड़ा है। अंधेरी अंडरपास में गंभीर जलजमाव को देखते हुए बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं और वहां पुलिस बल के साथ नगर निगम के कर्मचारियों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना को टाला जा सके।

मुंबई के आस-पास के इलाकों में भी लगा ट्रैफिक जाम

मुंबई के साथ-साथ उपनगरीय इलाकों कल्याण, डोंबिवली, नेरल और करजत में भी पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। इस तेज बारिश के कारण रेलवे ट्रैक और सड़कों पर पानी जमा होने लगा है। स्थानीय निवासियों को घरों से बाहर निकलते समय बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि आने वाले घंटों में बारिश की तीव्रता और बढ़ने की आशंका जताई गई है।

सायन हाईवे की स्थिति भी भयावह दिखी। एवरार्ड नगर सबवे में घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे स्थानीय निवासियों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने इस संवेदनशील इलाके से पानी निकालने के लिए बड़े-बड़े पंप चालू कर दिए हैं, लेकिन लगातार हो रही रिमझिम बारिश राहत कार्यों में बाधा डाल रही है।

लोकल ट्रेन का संचालन हुआ ठप

मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवाएं भी इस मूसलाधार बारिश से अछूती नहीं रही हैं। भारी जलभराव के कारण मुंबई की ट्रांस हार्बर रेल लाइन सेवा को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा है। इससे सुबह के समय अपने दफ्तरों और गंतव्य स्थानों के लिए निकले हजारों कामकाजी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि, मध्य और पश्चिमी रेलवे लाइनों पर ट्रेनें धीमी गति से संचालित हो रही हैं।

बेस्ट बसों के रूटों में किया गया बदलाव

सड़क परिवहन की बात करें तो बेस्ट (इएरळ) की बसों के रूटों में भी बदलाव किया गया है। सायन, गांधी मार्केट, दादर और हिंदमाता जैसे पारंपरिक रूप से संवेदनशील माने जाने वाले निचले इलाकों में पानी जमा होने के कारण ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से लगातार एडवायजरी जारी कर रही है। जिन इलाकों में जल-निकासी की रफ्तार धीमी है, वहां अतिरिक्त सफाई कर्मियों की टीमें तैनात की गई हैं।

नगर निगम की ओर से जारी बयान के अनुसार, हिंदमाता और मलाड सबवे जैसे संवेदनशील इलाकों में कुछ समय के लिए गंभीर स्थिति पैदा हो गई थी। पंपिंग स्टेशनों की सक्रियता की मदद से इन जगहों से पानी निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। गांधी मार्केट में भी पानी के स्तर को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक सक्शन पंपों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि स्थिति जल्द सामान्य हो सके।

मुंबई में 8 घंटों तक हुई रिकॉर्डतोड़ भारी बारिश

मुंबई और उसके अलग-अलग उपनगरों में 23 जून की रात 10 बजे से लेकर 24 जून की सुबह 6 बजे तक, यानी महज आठ घंटों के भीतर ही मुंबई के कई हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है। इतनी देर में शहर और उपनगरों के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए।

किन एरिया में कितनी हुई बारिश?

क्षेत्र	बारिश के आंकड़े (मिमी में) समयावधि
पश्चिमी उपनगर	190 मिमी 8 घंटे (रात 10 से सुबह 6 बजे)
मुंबई मुख्य शहर	184 मिमी 8 घंटे (रात 10 से सुबह 6 बजे)
पूर्वी उपनगर	154 मिमी 8 घंटे (रात 10 से सुबह 6 बजे)
पश्चिमी क्षेत्र (वेस्ट)	113 मिमी 20 घंटे के दौरान
पूर्वी उपनगर	8 7 मिमी 20 घंटे के दौरान
मुंबई शहर क्षेत्र	7 8 मिमी 20 घंटे के दौरान

मुंबई और आसपास के जिलों में रेड अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (क्टऊ) ने मुंबई और उसके आस-पास के जिलों के लिए अगले 24 से 48 घंटों के लिए गंभीर चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है। इसका सीधा मतलब है कि इन क्षेत्रों में अत्यंत भारी से बहुत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

इसके अलावा, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है, जबकि ठाणे जिले में मौसम की संवेदनशीलता को देखते हुए 'ऑरेंज अलर्ट' भी प्रभावी है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ-साथ तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने और समुद्र में ऊंची लहरें उठने की भी आशंका जताई है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है।

सीएम सम्राट चौधरी के हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान उड़ी 'धूल', बक्सर के बड़े अधिकारी सस्पेंड

(जीएनएस)।

कहते हैं कि एक छोटी सी चूक भी कभी-कभी बड़ी मुसीबत बन जाती है। बक्सर में कुछ ऐसा ही हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दौरे के दौरान हेलीकॉप्टर लैंडिंग के समय इतनी धूल उड़ी कि मामला सीधे सरकार तक पहुंच गया।

इसके बाद जांच हुई, रिपोर्ट बनी और अब नगर परिषद बक्सर के कार्यपालक पदाधिकारी कुमार ऋत्विक को सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि वीवीआईपी विजिट के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब यह मामला पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया है।

हेलीकॉप्टर उतरा नहीं, धूल का बादल छा गया

23 मई को बक्सर के किला मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कार्यक्रम था। हेलीकॉप्टर जैसे ही लैंडिंग के लिए नीचे आया, मैदान से भारी मात्रा में धूल उड़ने लगी। बताया जा रहा है कि मैदान की सही तरीके से सफाई नहीं हुई थी। धूल इतनी ज्यादा थी कि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग प्रभावित हो गई। मौके पर मौजूद अधिकारियों के बीच भी अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। बाद में इस पूरे मामले को सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल से जुड़ी बड़ी चूक माना गया।

ये भी पढ़ें; ढटउल्ल में अचानक पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, गायब मिले प्रिंसिपल, फोन भी नहीं उठाया, अब नपेंगे!

जांच टीम ने खोली पूरी कहानी

घटना के बाद जिला प्रशासन ने तुरंत जांच शुरू कर दी। एक स्पेशल टीम बनाई गई जिसने मैदान की तैयारी, सफाई व्यवस्था और अधिकारियों की जिम्मेदारी की जांच की। टीम ने अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी। रिपोर्ट में कई कमियां सामने आईं। जांच में पाया गया कि जिन तैयारियों को पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था, उनमें लापरवाही बरती गई। रिपोर्ट के आधार पर मामला राज्य सरकार तक पहुंचा और फिर एक्शन लिया गया।

इ४७१ के बड़े अधिकारी हुए सस्पेंड

जांच रिपोर्ट आने के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग ने बड़ा फैसला लिया। नगर परिषद बक्सर के कार्यपालक पदाधिकारी कुमार ऋत्विक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। विभाग का मानना है कि उनके स्तर पर जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं की गईं। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि किसी भी वीवीआईपी कार्यक्रम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सस्पेंशन के बाद प्रशासनिक महकमे में भी इस कार्रवाई की काफी चर्चा हो रही है।

सिक्योरिटी में चूक को Bihar सरकार ने माना गंभीर

सरकार का कहना है कि मामला सिर्फ धूल उड़ने का नहीं है। जब मुख्यमंत्री जैसे वीवीआईपी का दौरा हो, तब हर छोटी-बड़ी व्यवस्था का खास ध्यान रखना पड़ता है। हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान किसी भी तरह की परेशानी सिक्योरिटी रिस्क बन सकती है। इसी वजह से विभाग ने इसे गंभीर मामला माना। अधिकारियों को पहले ही जरूरी निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनके पालन में कमी मिलने के बाद सख्त कदम उठाया गया।

अभी और बढ़ सकती है मुश्किल

सस्पेंशन के बाद भी कुमार ऋत्विक की परेशानी खत्म होती नहीं दिख रही है। सरकार जल्द ही उन्हें चार्जशीट जारी कर सकती है और विभागीय जांच भी शुरू होगी। इस दौरान उनका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में तय किया गया है। वहीं बक्सर नगर परिषद में नए कार्यपालक पदाधिकारी की तैनाती की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। सरकार ने इस कार्रवाई के जरिए साफ कर दिया है कि प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही पर सीधे एक्शन होगा।